गरीबी और बेरोजगारी

- गरीबी-सामान्यतः जीवन,स्वास्थ्य तथा दक्षता के लिए कम से कम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने में सामाजिक क्रिया की अयोग्यता को गरीबी कहते है |
- जब समाज का एक बहुत बड़ा भाग न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने में असफल रहे तथा निर्वाह स्तर पर ही गुजारा करें तो इसे समाज में व्यापक गरीबी कहा जाता है |
- इन सभी अल्पविकसित देशों में जहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है,आय की इस असमानताओं ने कई बुराईयों को जन्म दिया है | जिसमें सर्वाधिक गंभीर बुराई है | गरीबी की अवधारणा बहुआयामी है |
- गरीबी से आशय जीवन की 'आधारभूत आवश्यकताओं' की पूर्ति से वंचित रहने से है |

गरीबी को दो रूपों में बाँटा जा सकता है :

- **साक्षेप गरीबी**
    - साक्षेप गरीबी स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गो के बीच कितनी विषमता है | इसको मापने के लिए विधियों का प्रयोग करते है |
- लारेंज व्रक विधि जिसे मैक्सओं लॉरेन्ज ने वर्ष 1905 में विकसित किया था |
- गिनी गुणांक विधि जिसे कोरैडो गिनी ने वर्ष 1912में विकसित किया था |
- **निरेपक्ष गरीबी**
- गरीब लोगों की संख्या क्या है इसकी जानकारी हमें निरेपक्ष गरीबी से प्राप्त होती है | इसके अंतर्गत एक निश्चित मापदंड के आधार पर तय करते है | कि कितने लोग इस मापदंड के नीचे है | उन्हें हम गरीब कहते है | इसके द्वारा गरीबी ज्ञात करने की विधि को हेड काउंटर विधि कहते है |
- विश्व बैंक विकासशील देशों में गरीबी रेखा के अनुमान के सम्बंध में 1 डॉलर प्रतिदिन आय को मानक के रूप में लेता थ ,अब वह 1.25 डॉलर प्रतिदिन आय को मानक के रूप में ले रहा है |
- एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1.35 डॉलर तथा भारत ने 1.02 डॉलर प्रतिदिन आय को मानक के रूप में लिया है |
- **गरीबी रेखा** : किसी परिवार के निर्वाह के लिए प्रति माह जितनी न्यूनतम आय चाहिए,वह धन गरीबी की रेखा कहलाता है | इससे कम आय प्राप्त करने वाले परिवार गरीबी रेखा के नीचे तथा इससे अधिक आय वाले परिवार गरीबी रेखा के ऊपर होते है |

भारत में गरीबी :

- भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण व्यक्ति की प्रतिदिन की कैलोरी की मात्रा के आधार पर किया जाता है |
- ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन के भोजन में 2400 में कैलोरी
- शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन के भोजन में 2100 में कैलोरी की मात्रा आवश्यक है |
- भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला अधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा जुलाई 1962 में किया गया और गरीबी रेखा के निर्धारण तथा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के निर्धारण के संबंध में एक कार्यदल का गठन किया गया |
- वर्ष 1977 में योजना आयोग द्वारा पुन: छठी योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता तथा प्रभावपूर्ण माखग के पूर्वानुमान के लिए एक कार्यदल गठित किया |
- वर्ष 1973-74 में योजना आयोग ने आहार प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों मेंरुपए 49.63 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्रों मेंरुपए 56.64 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की आवश्यकता होती थी |

लकड़ावाला फॉर्मूला

- योजना आयोग द्वारा देश में निर्धनता की माप के लिए वर्ष 1979 में प्रो० डी०टी० लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया |
- लकड़ावाला फॉर्मूला में शहरी निर्धनता के आकलन हेतु औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक व ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्देश्य हेतु कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया गया |

सुरेश तेंदुलकर समिति :

- निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की पहचान हेतु नए फॉर्मूले के निर्धारण हेतु वर्ष 2008 में गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को 2 दिसम्बर,2009 में प्रस्तुत की |
- समिति ने निर्धारण रेखा के निर्धारण हेतु अपनी फॉर्मूले में उपभोग व्यय को आधार बनाते हुए इसे अधिक व्यावहारिक बताया है |
- वर्ष 2004-05 में देश में 27% के स्थान पर 37% जनसंख्या को निर्धारता रेखा से नीचे माना जाता है |
- अब तक देश में निर्धनता रेखा के लिए जिस दांडेकरथ फार्मूले का इस्तेमाल वर्ष 1971 से किया जाता रहा उसमें भोजन में कैलारी की मात्रा को ही एक मात्र आधार माना जाता है |
- तेंदुलकर समिति के नए फार्मूले में कॉस्टऑफ लिविगं को निर्धनता की पहचान के लिए आधार स्वीकार किया है यह सभी राज्यों तथा शहरी और ग्रामीणके लिए अलग-2 होगी |

ग्रामीण गरीबी :

- भारत मेंग्रामीण गरीबी का मूल कारण कृषि में अल्पावधि या मौसमी उत्पादन संबंधों का होना है |
- आर्थिक संवृद्धि का लाभ स्वतः रिस-2 कर जनसंख्या के सभी वर्गों को प्राप्त हो जाता है जिससे गरीबी अपने आप कम हो जाती है | भारतीय कृषि के संबंध में इसका अर्थ है कि भूमि सुधारों के बिना भी कृषि उत्पादन में वृद्धि लाकर गरीबी के स्तर को कम किया जा सकता है | लेकिन यह संवृद्धि के लाभ पर आधारित होता है |

मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक :

- Human Development Report-1997 में मानव गरीबी सूचकांक को पहली बार स्पष्ट किया गया था | मानव विकास सूचकांक ने मानव जीवन के तीन मुख्य अभावों पर ध्यान केन्द्रित किया है | ये है -
    - प्रथम - जीवन की लम्बी अवधि न होना |
    - द्वितीय - ज्ञान का आभाव |
    - तृतीय - अच्छे जीवन स्तर का न होना |
- Human Development Report-2010 में मानव गरीबी का अनुमान लगाने के लिए एक नया बहुआयामी गरीबी सूचकांक को पहली बार शामिल किया जा रहा है |
- भारत में समय के साथ मुद्रास्फीति के कारण गरीबी रेखा को कीमतों में परिवर्तन के अनुसार पुनः परिभाषित किया गया |
- 2004-05 में पूरे देश के लिए गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में रुपए 356.30 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्रों में रुपए 538.60 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह माना गया है |

निर्धनता के अनेक कारण है जिनमे :

- बेरोजगारी,अल्पबेरोजगारी,कभी-2 काम मिलना,जनसंख्या वृद्धि,अनियमित मजदूरी कृषि और उद्योग में निम्न उत्पादकतास्तर आदि | ऋण-ग्रस्तता निर्धनता का एक महत्वपूर्ण कारक है |
- भारतीय संविधान तथा पंचवर्षीय योजनाओं ने सामाजिक न्याय को सरकार की विकास रण नीतियों का प्राथमिक उद्देश्य माना है | सरकार द्वारा निर्धनता निवारण के लिए त्रि-आयामी नीति अपनाई गई है |
- प्रथम कारक आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन तथा द्वितीय कारक लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है |

निर्धनता को दूर करने के उपाय :

- गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने कदम पर अनेक उपाय किए है |
- अन्त्योदय योजना (1977-78)में शुरू की गई जिसमें गरीब लोगों को कम कीमतों पर राशन मिलता है |
- 1985 में गरीब लोगों के लिए इंदिरा आवास-योजना |
- 2000 में अन्त्योदय अन्न योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को अत्यधिक कम मूल्य पर गेंहू,तेल ,चावल ,दालें आदि वितरित किया जाता है|
- राष्ट्रीय ग्रामीणरोजगार गारंटी कार्यक्रम (National Rural Employment Guarantee Act -NREGA) : इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी , 2006 को आंध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले में रनपाला मंडल के बंदापाली ग्राम पंचायत से किया था | उस समय 27 राज्यों के 200 जिलों में योजना की

शुरुआत की गई थी | नरेगा का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में पारिश्रमिक वाले रोजगार के सृजन से लोगों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना है | काम की गारंटी देने वाला यह अपनी तरह का विश्व का पहला कार्यक्रम है, जिसके तहत एक वित्त वर्ष में गाँव में कम से कम 100 दिन के काम की गारंटी दी गई है | यह अधिनियम सिर्फ एक कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि एक कानून है जिसके तहत रोजगार प्राप्त करने की कानूनी गारंटी दी गई है | अक्टूबर, 2000 में नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) कर दिया गया है और अब यह देश के सभी 600 जिलों में कार्यरत है |

- इस योजना के तहत एक परिवार में से केवल एक सदस्य को ही आवेदन करने का अधिकार होगा |
- इस योजना के अंतर्गत 33% रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है |

बेरोजगारी

- साधारणाभाषा में एक वर्ष में 8 घंटे प्रतिदिन की औसत से यदि 273 दिन तक किसी भी व्यक्ति के पास काम नही है तो वह बेरोजगार माना जाता है |
- भारतीय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने बेरोजगारी को परिभाषित किया कि यह वह अवस्था है, जिसमें व्यक्ति काम के अभाव के कारण बिना काम के रह जाते हैं |
- अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स जिन्होंने 1936 में अपने रोजगार सिद्धान्त में यह प्रतिपादित किया कि मन्दी की स्थिति में विकसित देशों में पायी जाने वाली बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में अधिउत्पादन या अर्थव्यवस्था में माँग या व्यय की कमी के कारण होती है | फलस्वरूप गंभीर बेरोजगारी की स्थिति दिखाई देती हैं |

बेरोजगारी के दो स्वरूप हैं-

- **ऐच्छिक बेरोजगारी**

  जब लोग स्वयं अपनी इच्छा से कार्य नहीं करना चाहतें है | ऐच्छिक बेरोजगारी होती है | जैसे-सन्त,भिखारी आदि |

- **अनैच्छिक बेरोजगारी**

  यह ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति चाहकर भी काम नहीं पाता है तो वह अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाता है |

विकसित देशों में दो प्रकार की बेरोजगारी पायी जाती है

- **चक्रीय बेरोजगारी :** चक्रीय बेरोजगारी यह व्यापार चक्र में शिथिलता के दौरान माँग में कमी के कारण उत्पन्न अस्थाई बेरोजगारी होती है |
- **घर्षण रहित बेरोजगारी :** इस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है, तो दोनों रोजगार के बीच की अवधि में बेरोजगारी हो जाता है | इस प्रकार की अस्थायी स्वभाव की बेरोजगारी की हम घर्षण रहित बेरोजगारी कहते है |
- विकासशील तथा अल्पविकसित देशों में जो बेरोजगारी पीयी जाती है वह संरचनात्मक होती है |

इसके अलावा भी बेरोजगारी अनेक प्रकार की होती है जिनके प्रमुख निम्नलिखित है -

- प्रच्छन्न बेरोजगारी- श्रम या मेहनत के अनुसार रोजगार नहीं |
- संरचनात्मक बेरोजगारी
- मौसमी बेरोजगारी- मौसम के आधार पर बेरोजगारी
- अल्प रोजगार-कुछ समय के लिए श्रम के अनुसार न होना |
- शिक्षित बेरोजगारी
- तकनीकी बेरोजगारी
- खुली बेरोजगारी
- चक्रीय बेरोजगारी
  - रोजगार की संरचना
  - इसकी निम्न प्रवृत्तियाँ है -
- रोजगार का व्यवसाय अनुसार वितरण -
  - इस रोजगार के अनुसार चार मुख्य क्षेत्र है -
- कृषि
- विनिर्माण
- व्यापार तथा सामुदायिक
- सामाजिक सेवाएँ
- कृषि में रोजगार में निरेपक्ष गिरावट हुई परन्तु कृषि ने सबसे बड़ा रोजगार व्यवसाय होने का अपना वर्चस्व बनाए रखा है |
- **संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में रोजगार**

HARYANA JOB ALERT

भारतीय अर्थव्यवस्था संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में विभाजित है असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है | सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र असंगठित क्षेत्र है | संगठित क्षेत्र विनिर्माण,बिजली,परिवहन तथा वित्तीय सेवाओं तक समीति है |

संगठित क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में बंटा है |

- **ग्रामीण एवं शहरी रोजगार :** कुल रोजगार में असंगठित क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि रोजगार की गुणवत्ता के सदंर्भ में चिन्ता का विषय है | इसका कारण है कि असंगठित क्षेत्र में वेतन कम,काम का बोझ ज्यादा,काम की दशाएं खराब तथा रोजगार सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा का आभाव होता है |

भारत में बेरोजगारी का स्वरूप :

- अन्य विकासशील देशों की तरह हो भारत में भी संरचनात्मक बेरोजगारी पायी जाती है | तो खुली तथा प्रच्छन्न दोनों रूपों में पाई जातो है |
- भारत में निश्चय ही अधिकांश बेरोजगारी ढ़ाँचागत है | संरचनात्मक बेरोजगारी के साथ-2 देश में चक्रीय बेरोजगारी भी है जो शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक मंदी की स्थिति के कारण पैदा हुई है |

भारत में बेरोजगारी की दो श्रेणियां है -

- बेरोजगारी की अवधारणएं- भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए निम्न अवधारणाओं को राष्ट्रीय सेंपल सर्वेक्षण संगठन और योजना आयोग द्वारा अपनाया गया है |
- **सामान्य स्थिति बेरोजगारी :** इस प्रकार की बेरोजगारी में यह जानने का प्रयास किया जाता है कि लोग सामान्यतया रोजगार में है या बेरोजगार है,अथवा श्रम शक्ति से बाहर है अर्थात् यदि कोई व्यक्ति वर्ष में 183 दिनों तक काम नहीं करता है,यह एक व्यक्ति दर और दीर्घकालीन बेरोजगारी दिखलाती है |
- **साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी :** इस अवधारणाके अनुसार यदि सात दिनों में कोई व्यक्ति किसी भी दिन एक घंटा भी काम प्राप्त कर सकने में समर्थ रहता है तो यदि रोजगार में मन लिया जाता है इसके विपरीत यदि एक भी घंटा काम नहीं किया हो तो वह बेरोजगार है |
- **दैनिक स्थिति बेरोजगारी :** इस अवधारणामें जब कोई व्यक्ति किसी दिन एक घंटे से अधिक और चार घंटे से कम काम करता है तो उसे आधे दिन कार्यरत माना जाता है चार घंटे से अधिक काम करने पर व्यक्ति को पूरे दिन कार्यरत माना जाता है |
- दैनिक स्थिति बेरोजगारी,बेरोजगारी का सर्वेक्षण माप प्रस्तुत करती है
- **शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी :** शहरी क्षेत्र में लगभग सभी बेरोजगारी प्रत्यक्ष है | शहरीक्षेत्र में बेरोजगारी दो प्रकार की है |
- औद्योगिक बेरोजगारी : औद्योगिक श्रमिकों में पायी जाने वाली बेरोजगारी मुख्यतयासंगठितक्षेत्र की है | इस क्षेत्र में पायी जाने वाली बेरोजगारी मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र के विकास की कम दर के कारण होती है |
- **शिक्षित बेरोजगारों :** इस प्रकार की बेरोजगारी मुख्यतः शहरी क्षेत्र में पायी जाती है इसका मुख्य कारण एक ओंर दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है जिसका व्यावसायिक पहलू कमजोर है और दूसरी ओंर रोजगार सृजन के अवसरों में धीमी वृद्धि है |
- **ग्रामीणक्षेत्र में बेरोजगारी :** वर्ष 2004-05 में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 8.0%थी |

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी :

- मौसमी बेरोजगारी : ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी एक सामान्य दशा है | खेतिहर मजदूरों के पास भी अवसर वर्ष रोजगार नहीं रहता है इस प्रकार की बेरोजगारी स्थायी स्वभाव की होती है |
- प्रच्छन्न बेरोजगारी : इस अवधारणासे तात्पर्य है कि खेत में उत्पादन के उच्च स्तर को पाने के लिए कुछ लोगों को खेती से हटा लेने पर भी कोई भी प्रभाव नही पड़ता है | उनके इस प्रकार के श्रम को फालतू श्रम कहते है | प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या का उल्लेख सर्वप्रथम श्रीमती जोन रॉबिन्सन ने किया था | इसका महत्वपूर्ण कारण जनसंख्या की वृद्धि तथा कृषि योग्य जोतों का कम होना |
- ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बेरोजगारी को मौसमी व प्रच्छन्न बेरोजगारी से अलग करके देखना बहुत कठिन है |
- हमारी मिश्रित पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व सहकारी क्षेत्र,सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार संवृर्द्धन के प्रति अपना संकल्प व्यक्त किया गया है |
- **बेरोजगारी के अनुमान के संबंध में दो समितियाँ उल्लेखनीय है-**

  1.दाँतेवाला समिति

2.भगवती समिति

- ग्रामीण एवं शहरी गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के सरकारी कार्यक्रम:

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

- यह कार्यक्रम छठी योजना में शुरू किया गया और इसे सातवीं योजना में भी लागू रखा गया |
- 2 अक्टूबर,1980 से 'काम के बदले अनाज योजना' को राष्ट्रीय ग्रामीण योजना में विलय करके लागू किया तथा 1 अप्रैल,1989 को इसे जवाहर रोजगार योजना के साथ मिला दिया गया |
    - टाइसेम
- ग्रामीण युवा वर्ग के लिए यह कार्यक्रम 15 अगस्त,1979 को शुरू किया गया | इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (जिनकी आय 3500 रूपया वार्षिक से कम है) 18-35 वर्ष के युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है |
- 1 अप्रैल,1999 में इस योजना का विलय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कर दिया गया |

जवाहर रोजगार योजना

- ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों की श्रृंखला में इस महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत 1988-90 के बजट में की गई थी |
- इसमे ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा खेतिहर मजूदर रोजगार गांरटीकार्यक्रम को विलय कर दिया गया था |
- अप्रैल 1999 में जवाहर रोजगार योजना को पुनगर्ठित कर इसे जवाहर ग्राम संमृद्धि योजना का नाम दिया गया |

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

- इस अप्रैल 1999 में शुरू किया गया | वर्तमान में यह योजना एकमात्र स्वरोजगार कार्यक्रम है इसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों,जो स्वरोजगार में लगे है,ऐसे लोगों को बैंकों से ऋण व सरकारी आर्थिक सहायता के तहत ऋण उपलब्ध कराना है |

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

- 25 सितम्बर,2001 में जवाहर ग्राम संमृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना को मिलाकर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की गई | इस कार्यक्रम को पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा लागू किया जाता है | यह अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने वाली योजना है | इसका एक अन्य कार्य खाद्य सुरक्षा का भी है अप्रैल,2008 में SGRY को मनरेगा में सम्मिलित कर दिया गया है |

इंदिरा आवास योजना

- ग्रामीण भूमिहीन अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के सदस्यों तथा मुक्त बंधवा मजदूरों को बिना मूल्य के आवास उपलब्ध कराना | इसे 1985-86 में शुरू कर 1 अप्रैल,1989 को जवाहर योजना के रूप में बनाया गया |

स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना

- दिसम्बर 1997 में शहरी रोजगार और गरीबी निवारण को विभिन्न योजनाओं के स्थान पर आरंभ की गई | 1 अप्रैल,2009 को इस योजना पुनर्गठन किया गया |

पुनगर्ठित के पाँच हिस्से है-

- शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम
- शहरी स्त्री स्वसहायता कार्यक्रम
- शहरी गरीबों में रोजगार प्रोत्साहन के लिए कौशल प्रशिक्षण|
- शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम
- शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क |

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम

- यू०पी०ए० सरकार द्वारा अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम के दौरान नरेगा सितम्बर 2005 को पारित हुआ | 2 फरवरी,2006 को प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह द्वारा आंध्रप्रदेश के बन्दापाली से शुरू की गयी |

HARYANA JOB ALERT
हर सवाल का जवाब!

- शुरू में यह योजना देश के 200जिलों में लागुब्की गयी थी | इसके दूसरे चरण 2007-08 में और 130 जिलों में तथा तीसरे चरण 1 अप्रैल,2008 से बाकी सभी 247 जिलों में लागू कर दिया गया | इस प्रकार अब देश के सभी 619 जिलों में नरेगा कार्यरत है |
- यह अन्य सभी रोजगार प्रदान करने वाली स्कीमों से भिन्न,यह संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने की गारंटी के साथ कानून द्वारा अधिकार प्रदान करती है |
- 2 अक्टूबर,2009 से इसका नाम बदलकर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कर दिया गया |
- वर्तमान में यह योजना पूरे देश में लागू है |
- इस नियम के आधार पर किसी एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ऐसे ग्रामीण परिवार के एक व्यस्क को कम से कम 100 दिन रोजगार की गारंटी प्रदानकरता है जो अकुशल शारिरिक श्रम के लिए तैयार है |
- ग्राम पंचायत इस स्कीम की क्रियान्वयन इकाई है तथा परिवार लाभ प्राप्तकर्ता इकाई है |
- इसमे दी जाने वाली मजदूरी प्रत्येक राज्य में घोषित न्यूनतम मजदूरी के बराबर है |
- रोजगार के लिए आवेदनकर्ता को 15 दिन के भीतर रोजगार प्रदान किया जायेगा,जो श्रमिक के निवास स्थान से 5 किलोमीटर दूरी के भीतर होगा | इससे अधिक दूर काम मिलने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी |
- जॉब कार्ड के प्राप्त होने के 15 दिन तक यदि कार्य नही प्राप्त होता तो वह बेरोजगारी भते का हकदार है |
- जॉब कार्ड 5 वर्षो के लिए माना जाएगा |
- लाभ प्राप्त कर्ताओं में 33% स्त्रियां होनी चाहिए |
- MGNREGA के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान बैंकों या पोस्ट ऑफिस में खातों के माध्यम से करना अनिवार्य है | जिसमें होने वाले व्यय को केन्द्र और राज्य सरकारे 90:10 के अनुपात में वहन करेगीं |
- MGNREGA में कार्य प्राकृति के अधीन,जल संरक्षण,सूखाग्रस्त क्षेत्रों का उद्धार,भूमि विकास,बाढ़ नियंत्रण,तथा सभी मौसमों में काम आने वाली सड़कों का निर्माण इत्यादि कार्यक्रम बिना ठेकेदारों और मशीनरी का प्रयोग द्वारा पूरा किया जायेगा |
- 2 फरवरी को सरकार ने रोजगार दिवस घोषित किया है |

स्त्रियों के सशक्तिकरण या विकास से संबधित योजना-

- स्वसहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के विकास तथा सशक्तिकरण की यह एक समन्वित योजना है |

स्वावलंबन:

- 27 सितम्बर,2010 वित्तीय मंत्री प्रणव मुखर्जी द्वारा चलाई गई इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को प्रशिक्षण तथा कुशलता प्रदान करना जिससें वह स्वरोजगार पा सकें |

स्वाधार:

- वर्ष 2001-02 में शुरु की गयी एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है | इसमें विभिन्न परिस्थितियों में तस्त जैसे परिवार में त्यक्त विधवाओं,जेल से छुट्टी,बेघर आदि महिलाओं के सुधार के लिए यह योजना है |

महिला समख्य:

- इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को शक्तिमान बनाना जिससे बिना किसी थोड़ी बाहर सहायता के वे अपने सामूहिक कार्यक्रम को चला सकें |

अन्नपूर्णा योजना:

- 2 अकटूबर,2000 के बजट में अन्नपूर्णा योजना का आरंभ गांजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से हुआ था | इनका उद्देश्य अत्यतं निर्धन लोगों के लिए रोटी की व्यवस्था करना | 2001-02 में बजट में संशोधन के अनुसार अब जो वृद्धावस्था पेंशन पा रहें हैं वे भी लाभांवित होंगे |

अन्योदयअन्नपूर्णा योजना

- दिसम्बर 2000 में चालू की गयी इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसमे BPL परिवार को 2000 से 25 किग्रा को बढ़ाकर 35 किग्रा.अनाज-गेहूं 2 रुपए तथा चावल 3 रुपए प्रति किग्रा. की दर से दिया जाता है |

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

- 25 दिसम्बर, 2000 को चालू की गयी |यह पूर्णत: केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका वित्त पोषण डीजल पर उपकार से होता है | इस योजना का उद्देश्य 500 से अधिक आबादी वाले गाँवों को हर मौसमी सड़क से जोड़ना है |

देवी रूपक योजना:

- हरियाणा सरकार द्वारा 25 दिसम्बर, 2007 से राज्य में जनसंख्या के नियंत्रण के साथ-साथ लिंगानुपात में गिरावट को रोकना था |
  - स्वजलधारा परियोजना :
- 25 दिसम्बर, 2002 देश के ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई |

मिड-डे-मील :

- 15 अगस्त, 1955 को शुरू केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है | इसका उद्देश्य सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकायों के प्राइमरी स्तर कर बच्चों को निःशुल्क भोजन प्रदान करना |

Empowering Youth Empowering Nation
HARYANA JOB ALERT
हर सवाल का जवाब!

निर्धनता एवं बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम एवं परियोजनाएं

❁ योजना/ कार्यक्रम	❁ शुभारंभ	❁ लक्ष्य	❁ उद्देश्य	❁ अतिरिक्त जानकारी
❁ 1.सामुदायिक विकास योजना	❁ 1952-53	❁ जन सुविधाओं में वृद्धि	❁ गांव में कृषि.पुशपालन,ग्रामोद्योग स्वास्थ्य और उपचार एवं बाल कल्याण आदि क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना |	❁ इस योजना को यद्यपिआशा के अनुरूप सफलता नहीं मिल सकी लेकिन इससे प्राप्त अनुभव के आधार पर गांवों मेंप्रशासनिकविकेन्द्रीकरण की आवश्यकता महसूस की गई और बलवंत राय मेहता कमेटी भी गठित की गई |
❁ 2.ग्रामीण विदघतीकरण योजना	❁ 1969-70	❁ ग्रामीण विद्युतीकरण	❁ देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में यथाशीघ्र बिजली पहुचाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना |	❁ जुलाई,1969 से ग्रामीण विद्युतीकरण करके ग्रामीण क्षेत्र को विकेन्द्रीकरण निगम की स्थापना करके ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर विदयुतीकृत करने का प्रयास किया गया है | अभी तक 13 राज्य शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुके हैं |
❁ 3.ऑपरेशन फ्लड योजना	❁ 1970	❁ दुग्ध विकास	❁ दुग्ध उत्पादकों को विचौलियों के शोषण से मुकित दिलाने हेतु आनन्द पद्धति पर	❁ दुग्धशाला विकास की एक राष्ट्रीय योजना के रूप प्रांरभ की गयी इस योजना को श्वेत-क्रांति के लिए उत्तरादायी माना जाता है |

HARYANA JOB ALERT
हर सवाल का जवाब!

			ग्राम्य स्तर की सहकारी दुग्ध समितियाँ गठित करके उनके ही माध्यम से सीधे दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध उपार्जन कराना ।	
❁ 4.आँगन वाड़ी पोषाहार योजना	❁ 1970-71	❁ बाल कल्याण	❁ 3 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पूरक पोषाहार, मनोरंजन सुविधाएं और अनौपचारिक स्कूल ।	❁ केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर के स्वयंसेवी पूर्व शिक्षा प्रदान करना । सगंठनों द्वारा संचालित किया जा रहा है ।
❁ 5.मरूस्थल विकास कार्यक्रम	❁ 1997-78	❁ रोजगार सृजन के अंतर्गत विलय	❁ मरूस्थलीय क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय संतुलन बहाल करते हुए वहा श्रम आधारित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ।	❁ शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से संचालित इस कार्यक्रम पर विकास खंडों में 277 करोड़ रूपए से अधिक राशि व्यय की जा चुकी थी ।

❁ 6.काम के बदले अनाज योजना	❁ 2004	❁ रोजगार सृजन	❁ राज्यों के स्टॉक में उपलब्ध खाद्यान्न का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करते हुए विकास कार्य करना		❁ दो वर्ष तक चलाये गये इस कार्यक्रम में 9 करोड़ 50 लाख मानव दिवसों का कार्य सृजित किया गया	
❁ 7.अंत्योदय अन्न योजना	❁ 2000	❁ रोजगार सृजन	❁ गाँव में रहने वाले गरीब परिवारों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी		❁ यह योजना विशेष रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर सकी	
❁ 8.राष्ट्रीय ग्रामीण योजना	❁ 1983-81	❁ रोजगार सृजन	❁ ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराते हुए गाँवों में स्थायी तथा उत्पादक		❁ केन्द्र तथा केंद्र सरकार की बराबर की भागीदारी से यह योजना मार्च,1989 तक चलाई गई	1 अप्रैल,1989 से इसे जवाहर योजना में विलय कर दिया गया	

			परिसंपत्तियों का सृजन करना तथा भूमिहीन कृषक परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना |	
❁ 9.ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यकाल	❁ 1985-84	❁ रोजगार सृजन	❁ ग्रामीण भूमिहीनों .के परिवारों. में कम से कम एक सदस्य को न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना |	❁ इस योजना में केन्द्र सरकार ने राज्यों को प्रारंभ में ही 500 करोड़ रूपयों का ही धनावंटन किया और उसकी उपयोजना के रूप में इंदिरा आवास योजना को संचालित करने का निर्णय लिया गया |
❁ 10.किशोरी बालिका योजना	❁ 1985-86	❁ बालिका विकास	❁ गरीब परिवारों की किशोरी बालिकाओं को	❁ इस योजना को समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है |

			उनके सामान्य स्वास्थ्य टीकाकरण,स्वास्थ्य पोषण,आम बिमारियों के इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य विकास को सुनिश्चित करना |	
❁ 11.इंदिरा आवास योजना	❁ 1985-86	❁ आवासीय सुविधा	❁ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों को मकान बनवाने हेतु निःशुल्क सहायता के रूप में सरकार द्वारा निधार्रित धनराशि प्रदान करना |	❁ इस योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है योजना जो 80:20 के अनुपात में केन्द्र और राज्य सरकार को आर्थिक सहयोग से चलाया जा रहा है |
❁ 12.ग्रामीण	❁ 1986-	❁ स्वरोजगार	❁ ग्रामीण क्षेत्रोंमेंसु	❁ मुख्यतः केन्द्र सरकार के वित्तीय अनुदान से अब

HARYANA JOB ALERT
हर सवाल का जवाब!

विकास की 'कपार्ट' योजना	87	सृजन	मचित विकास और वहाँ आर्थिक गातिवि धियों को प्रोत्साहि तकरने हेतु स्वैच्छिक कार्यकला पोंकोअभि प्रेरित करना |	तक 18 हजार से भी अधिक परियोजनाओं को संचालित कराया गया है |
❁ 13.जवाह र रोजगार योजना	❁ 198 8-90	❁ स्वरो जगार सृजन	❁ ग्रामीण पुरूषों और महिला को अतिरि क्त रोजगार उपलब्ध कराकर गाँवों में सामुदायि क परिसंप त्तियों का निर्माण करना तथा ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाना |	❁ केन्द्र और राज्य सरकार 80:20 के आर्थिक सहयोग से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को सम्मिलित करके इस नई योजना को संचालित किया जिसमें कुल 1800 करोड़ रुपए व्यय करके 29 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया |
❁ 14.महि ला समख्य योजना	❁ 198 9-90	❁ महि ला सश क्तिक	❁ महिला को शिक्षा प्रदान करते हुए	❁ उत्तर प्रदेश,गुजरात,कर्नाटक,आन्ध्र प्रदेश,बिहार,असोम,मेघालय, के चयनित 5500 गाँवों में

HARYANA JOB ALERT
हर सवाल का जवाब!

		रण	उन्हें समान अधिकार दिलाने तथा उनके सशक्ति करण के लिए प्रयास करना |	यह योजना संचालित की गई है |
❁ 15.ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	❁ 1990-91	❁ स्वच्छ शौचालय निर्माण	❁ ग्रामीण लोगों को वहाँ गदें पानी और गदंगी से फैलने वाले रोगों के संबंध में शिक्षित करना और सुरक्षा प्रदान करना और गरीब ग्रामीण को अपने घरों में व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालय निर्माण कराने हेतु आर्थिक तथा तकनीकी सहायता	❁ यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ पंचीयतीराज विभाग के सहयोग से 35:35:30 के आर्थिक सहयोग से चलाई गई है |

HARYANA JOB ALERT
हर सवाल का जवाब!

			प्रदान करना |	
❁ 16.महिल संवृद्धि योजना	❁ 1993-94	❁ महिला सशक्तिकरण	❁ ग्रामीण महिलाओं को डाकघर बचत खाते में छोटी-छोटी बचतें जमा करने हेतु प्रोत्साहित कर उनमें बचत की आदत डालना |	❁ रस योजना को वर्ष 1997-98 तक चलाया गया और 1 अप्रैल,1998 से बंद कर दिया गया |
❁ 17. बाल श्रम उन्मूलन योजना	❁ 1993-94	❁ बाल श्रम निवारण	❁ खतरनाक उद्योगों में लगे बाल श्रमिकों को श्रम क्षेत्र से हटाकर उन्हें स्कूल भेजना तथा रोजगार संबधी प्रशिक्षण प्रदान करना |	❁ केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह योजना सभी राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है |
❁ 18.प्रधान मंत्री रोजगार योजना	❁ 1994-95	❁ स्वरोजगार विकास	❁ शिक्षित बेरोरोजगार युवाओं को उद्योग,	❁ इस योजना को वर्ष 1997-98 तक चलाया गया और 1 अप्रैल,1998 से बंद कर दिया गया |

HARYANA JOB ALERT
हर सवाल का जवाब!

			सेवा तथा कारोबार के क्षेत्र में स्वरोजगार उपलब्ध करने हेतु लघु इकाईयों को स्थापित किया जाना	
❁ 19.मध्याह्व भोजन योजना	❁ 1995-96	❁ शैक्षिक विकास	❁ प्राथमिक विदयालयो में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को अधिक से अधिक नामांकित होने के लिए आकर्षित करना व अनुकूल पोषाहार निशुल्क उपलब्ध कराना	❁ यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता से राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की गई	अब यह योजना 1 से 8वीं तक बच्चों को अनुकूल पोषाहार उपलब्ध कराती है
❁ 20.पल्स पोलियों कार्यक्रम	❁ 1997-98	❁ बालकों में प्रतिक्षण	❁ पुरे देश में पाँचवर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियों से मुक्त	❁ इसके जरिए देश से पोलियो खत्में में उल्लेखनीय सहायता मिली है	

HARYANA JOB ALERT
हर सवाल का जवाब!

			रखने के लिए दवा पिलाना ।	
❁ 21.स्वर्ण जयन्ती ग्राम योजना	❁ 1997-98	❁ जन सुविधओं का विकास	❁ देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के उपलब्ध में प्रत्येक विकास खंड में एक स्वर्ण जयंती ग्राम को एक चयन करके ऐसे गाँवों को एक आर्दश ग्राम के रूप में पूर्णरूपेण विकसित करना ताकि उसका अनुसरण किया जा सकें ।	❁ इस योजना के विकासखंड में ऐसे सबसे पिछड़े और उपेक्षित गाँव का चयन किए जाने का प्रावधान रखा गया जो किसी स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा हो ।
❁ 22.स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना	❁ 1999-2000	❁ स्वरोजगार विकास	❁ ग्रामीण गरीबों को स्वयं-सहायता समूह के गठन के माध्यम से उन्हें स्वरोजगा	❁ IRDP,टाइसेम,इवाकरा,सिटा, गंगा कल्याण योजना तथा मिलियन वैल स्कीम को समन्वित करके 1 अप्रैल,1999 से स्वर्ण जयंती रोजगार योजना को संचालित किया है ।

Empowering Youth Empowering Nation
HARYANA JOB ALERT

			र उपलब्ध कराते हुए सामथ्र्य प्रदान करने के नियमित गाँवों में छोटे-2 उद्योग की स्थापना करना |	
❁ 23.अन्न पूर्णा योजना	❁ 1999-2000	❁ वृद्धाव स्था सहाय ता	❁ निराश्रित वृद्धों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम गेहूँ/चाव ल निःशुल्क प्रदान करते हुए उन्हें समान जीवन बताने योग्य बनाना |	❁ इस योजना में केंद्र सरकार की शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता से राज्यों द्वारा क्रियान्वित किए जाने का प्रावधान किया गया है |
❁ 24.प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना	❁ 2000-2001	❁ जन सुविध ओं का विका स	❁ गाँवों में एक समयबद्ध कार्यक्रम चलाकर ग्रामीण लोगों की बुनियादी आवश्यक ताओं को पूरा	❁ केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा वर्ष 2000-2001 के बजट सत्र की में की गई है |

			करना |	
❁ 25. सर्वशिक्षा अभियान	❁ 2001	❁ सभी को शिक्षा	❁ इसके तहत 6-14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 8वीं तक गुणवत्ता पूर्ण निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है |	❁ इस योजना पर केन्द्र व राज्य सरकार 50;50 के अनुपात में वित्तीय भार बल करेगी |सभी को शिक्षा उपलब्ध करवाने की दिशा में UNESCO ने 2015 तक की सीमा निर्धारित की है |
❁ 26. भारत निर्माण योजना	❁ 2005-06	❁ ग्रामीण आधार संरचना	❁ समावेशी विकास के लिए ग्रामीण आधार संरचना का विकास	❁ इस प्रोग्राम के मुख्य लक्ष्य में सिंचाई,ग्रामीण जुड़ाव,ग्रामीण पेयजल,ग्रामीण गृह-निर्देशक और ग्रामीण टेलीकॉम क्षेत्रों के बुनियादी ढांचें का विकास करना शामिल है |
❁ 27. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय योजना	❁ 2005	❁ शहरी आधार संरचना	❁ आधार संरचना सेवाओं का समन्वित विकास	❁ इस योजना पर 50,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जायगें | 35 महानगरों में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रोजेक्ट-लागत के 100% अनुदान के रूप में दी जाएगी और उत्तर पूर्वी राज्यों में 90% के आधार पर |
❁ 28.महात्मा गांधी नरेगा योजना	❁ 2006	❁ रोजगार सृजन	❁ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना |	❁ राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम के नाम से शुरू हुई इस परियोजना का नाम बाद में महात्मा गाँधी के नाम पर कर दिया गया | इसमें ग्रामीण परिवारों के काम करने के इच्छुक व्यक्तियों को कम से कम 100 दिन के

HARYANA JOB ALERT
हर सवाल का जवाब!

				रोजगार की गारंटी दी जाती है ।
❁ 29.राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण योजना	❁ 2010	❁ किशोरियों का सशक्तिकरण	❁ किशोरियों का घर ले जाने के लिए राशन मुहैया कराना ।	❁ योजना के तहत स्कूल जाने वाली 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग वाली लडकियों तथा 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग वाली सभी लडकियों को साल के 300 दिन पाँच रुपए प्रति लाभार्थी की दर पर पोषण संबधी प्रावधान (600 कैलोरी और 18 से 29 ग्राम प्रोटीन है जिसकी आधी-आधी (50;50) लागत केन्द्र व राज्य सरकार वहन करेंगी ।

Empowering Youth
Empowering Nation
HARYANA JOB ALERT
हर सवाल का जवाब!